दुग्ध योजना ने निम्नलिखित उपाय अपनाये है :—

(1) जो ठेकेदार दिल्ली दुग्ध योजना को दूध का संभरण करते है उनके साथ पक्के करार कर दिये गये है। वे वर्ष में स्वीकार की हुई दूध की मात्रा के सम्भरण न करने पर 5 रुपये प्रत्येक क्विन्टल की दर पर अब दंड के भागी होंगे।

(2) ठेकेदारों को प्रोत्साहन देने के लिये, उनको दी जाने वाली कमीशन की दर बढ़ा दी गई है।

(3) दिल्ली दुग्ध योजना का उपलब्धि क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में करनाल में लगभग 20 मील की दूरी पर एक नया उपलब्धि क्षेत्र शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर और राजस्थान में अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों से भी दूध संचयन शुरू किया गया है।

(4) दिल्ली दुग्ध योजना के क्षेत्र के लिए, जिला मेरठ (यू० पी०), गुड़गांव और कसाल (हरियाणा), तथा बीकानेर (राजस्थान) में चार सघन पशु विकास कार्य क्रम मंजूर किए गए हैं।

(5) करनाल में सघन पशु विकास कार्यक्रम की सहकारी समितियों का संगठन कार्य, सघन आधार पर शुरू कर दिया गया है। इन समितियों के उत्पादक सदस्यों को दुधारू जानवर खरीदने के लिये ऋण दिये जा रहे है।

(6) हरियाणा के रोहतक जिले में एक पशु विकास योजना तैयार की गई है जो कि दिल्ली दुग्ध योजना के पास उपलब्ध विश्व खाद्य कार्यक्रम की निधि से पूरी की जायेगी।

(7) यथा समय मेहसाना जिला सहकारी दुग्ध-उत्पादक यूनियन, मेहसाना (गुजरात) से प्रतिदिन 1,00,000 लिटर तक दूध खरीदने का प्रबन्ध किया गया है। पिछले दिसम्बर से मेहसाना यूनियन से दूध का संभरण शुरू हो गया है और इस समय उनसे लगभग औसतन 15,000 लिटर दूध प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है।

(8) दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय दुग्धशाला का विस्तार इसकी अनुकूलतम प्रबन्ध क्षमता तक किया जा रहा है। पहली अवस्था में केन्द्रीय दुग्धशाला की मूल क्षमता प्रतिदिन 2,55,000 लिटर से 3,00,000 लिटर तक और दूसरी अवस्था में 4,35,000 लिटर तक बढ़ाई जा रही है।

(9) राजस्थान में बीकानेर स्थान पर एक संतुलन स्टेशन बनाया जा रहा है जिसकी क्षमता प्रथम अवस्था में प्रतिदिन 50,000 लिटर होगी।

(10) योजना की प्रबन्ध समिति तथा शासी निकाय ने दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दूसरी दुग्धशाला खोलने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ग) दिल्ली की जनसंख्या के बड़े भाग को दिल्ली दुग्ध योजना की सेवा यथा सम्भव उपलब्ध कराने के लिये, दिल्ली दुग्ध योजना की उपलब्धि तथा प्रबन्ध क्षमता बढ़ाने की भरसक कोशिश की जा रही है। फिर भी, ठीक ठीक यह कहना कठिन है कि ऐसा जल्दी से जल्दी कब तक किया जा सकेगा।

State Trading in Foodgrains

*251. SHRI D. AMAT :
SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA :

SHRI G. C. NAIK :
SHRI J. K. CHOUDHURY :

Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether the State Trading in foodgrains has resulted in a loss ;

(b) if so, the amount of loss incurred during the year 1967-68 ;

(c) the reasons for the loss ; and

(d) the steps taken to avoid such losses in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 93.69 crores.

(c) The loss in the State Trading in foodgrains has been on account of distribution of foodgrains by the Central Government at issue prices lower than the economic costs of these foodgrains. This loss thus represents the subsidy involved in the distribution of foodgrains by the Government.

(d) The Government have been gradually raising the issue prices of foodgrains to the levels of their economic costs in order to red uce the quantum of subsidy. At present the distribution of imported rice ane imported milo only is being subsidised. With the improvement of food situation and lesser imports from abroad in the future, the quantum of subsidy is likely to be further reduced and finally completely abolished.

Demands of Jute Industry Workers

*252. SHRI J. M. BISWAS :
SHRI RAMAVATAR SHASTRI :
SHRI S. M. BANERJEE :

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Jute Mills' Association had rejected even a modest request for an ad hoc increase of Rs. 24 per worker made by him at the last meeting of the Industrial Committee on Jute ;

(b) whether it is also a fact that tripartite conference also took place on the demands of the Jute Industry Workers ; and

(c) if so, the outcome of this tripartite conference ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI BHAGWAT JHA AZAD) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Tripartite talks held at State level to consider the demands of the workers have also not been successful so far.

दिल्ली में एक अन्य डेरी की स्थापना

253. **श्री झा० सुन्दरलाल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक और सरकारी डेरी स्थापित करने की योजना तैयार की गई है और क्या इसके लिये स्थान भी चुन लिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसके लिये किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने से कितना लाभ होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना की प्रबन्ध समिति और शासी निकाय ने दिल्ली में दूसरी डेरी स्थापित करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है । इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा अभी विचार किया जाना है। इसके लिये अभी स्थान नहीं चुना गया है ।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना ने इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया है । इस समय तक जमुना पार पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली विकास अधिकरण द्वारा पेश की